



②

~~24~~      719 (22)

②

dia)  
5  
N  
|  
r  
ani  
|  
49

(2) उपधारा (9) के अधीन उद्गृहीत तबों संगृहीत भासा भवन उपकर उस भू-राजस्व या लगान या किसी अन्य उपकर या कर के प्रतिरूपत होगा जो भूमि के धारक द्वारा उस खाले के संघ में संहिता के अधीन या सरसमय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिती के अधीन तबों और भूमि के धारक द्वारा भू-राजस्व के साथ उसी रीति में देय होगा जिस रीति में कि भू-राजस्व देय होता है।

(3) संहिता के ये उपखण्ड, जो भू-राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली से संबंधित हैं, जहां तक हो सके; इस भाग के अधीन के शाला सभन उपकर के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली को उसी प्रकार लागू होंगे मानी वह उपकर उस खाले पर संहिता के अधीन निर्धारित भू-राजस्व हो।

4. (9) धारा 3 के अधीन के शाला भवन उपकर के आरम्भ प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायेंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेंगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए शाला भवन उपकर के प्रागर्भों के समतुल्य हो, और उसे प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित न्यय होगी।

(2) राज्य सरकार प्रतिवर्ष निधि में अपना प्रभिदाय करेगी जो उपधारा (9) के अधीन निधि में जमा की गई रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगा।

(3) निधि में जमा रकम का उपयोग, संहिता की धारा 2 के खण्ड (घ-4) में यथापरिभाषित नगरेतर क्षेत्रों में प्राथमिक शाला भवन का सन्निर्माण करने तथा उसे सुसज्जित करने के लिए किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए किसी जिले को निधि में जमा रकम में से केवल उतनी रकम, जितनी कि उस जिले से शाला भवन उपकर के रूप में वसूल हुई हो, उस जिले के लिए राज्य सरकार के प्रभिदाय के पचास प्रतिशत सहित, आवंटित की जाएगी।

5. प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि का संभारण और परिचासन, जिसके अन्तर्गत इसमें जमा राशियों का विनिधान या पुनर्विनिधान आता है, इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

भवन विकास उपकर

6. इस भाग में,—

- (क) "भवन विकास उपकर" से अभिप्रेत है धारा 6 के अधीन वन विभाग द्वारा वन-उपज के विक्रय का प्रदाय पर उद्गृहीत उपकर;
- (ख) "वन विभाग" के अन्तर्गत आता है कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 9) के अधीन गठित वन विकास निगम;
- (ग) अभिव्यक्ति "वन-उपज" का वही अर्थ होता जो कि उक्त अधिनियम के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 96) की धारा 2 के खण्ड (4) में दिया गया है।

विक्रय  
र वन  
र कर

(9) वन विभाग द्वारा वन-उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर, उस कीमत के, विल पर कि ऐसी वन-उपज बेची जाती है या उत्तरक प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा।

(2) उपधारा (9) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकर किसी ऐसे कर के प्रतिरूपत होगा जो वन-उपज पर सरसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्गृहीत है।

(3) वन विभाग द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई वन-उपज के संबंध में उपधारा (9) के अधीन देय वन विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन-उपज बेची जाती है या जिसको उसका प्रदाय किया जाता है और उसका संग्रहण तथा वसूली वन विभाग के उस अधिकारी या पर्यधिकारी द्वारा, जो ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित हो, करी समय किया जाएगा जबकि ऐसा विक्रय या प्रदाय किया जाता है।

(१) के अधीन उद्गृहीत वन भिक्षा उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संघित निधि में जमा करके, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, विधि द्वारा सम्पत्ति विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, निधि में उतनी रकम प्रत्याहृत कर ली जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाई गए प्रयोगों के समतुल्य हो, और उक्त वन भिक्षा निधि नामक एक पुनर्निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य की संघित निधि पर आरित करेगी।

- (१) उक्त निधि में जमा रकम का उपयोग, राज्य सरकार के विनियमानुसार, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करेगा—
- (अ) सामाजिक वानिकी प्रयोजन।
- (ब) कर्मरोपण, पुनर्बनरोपण तथा कर्मों का पुनरुद्धार; और
- (२) कर्मों के विकास से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनियमित करेगी।
- (३) अंतर्विषय निधि का संधारण और परिवर्तन इस निहित बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

**भाग ४—खनिज क्षेत्र विकास उपकर.**

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ.

- (अ) "अनिवार्य भाटक" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय अनिवार्य भाटक;
- (ब) "भूमि" से अभिप्रेत है खनिज संक्रियामें चलाने के लिए खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि;
- (ग) "खनिज क्षेत्र विकास उपकर" से अभिप्रेत है खनिज संक्रियामें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर धारा २ के अधीन उद्गृहीत उपकर;
- (घ) "स्वामित्व (रायल्टी)" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय स्वामित्व (रायल्टी) और उसके अन्तर्गत उस भूमि में से खनिज निकालने के अधिकार के लिए उक्त अधिनियम के अधीन धारित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को किये गये या किये जाने के लिये संभाव्य कोई संशय आते हैं;
- (ङ) उन शर्तों तथा अधिव्यक्तियों के, जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं तथा जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) में परिभाषित की गई हैं, वे ही कार्य होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

- (१) खनिज संक्रियामें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर, उस भूमि के भाटक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा।
- (२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, भाटक मूल्य यद्यत्स्थिति स्वामित्व (रायल्टी) या अनिवार्य भाटक, तब से भी अधिक हो, के बराबर होगा।
- (३) खनिज क्षेत्र विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसे खनन पट्टा अगुवत किया जाता है।
- (४) खनिज क्षेत्र विकास उपकर का संग्रहण ऐसे अधिकारियों द्वारा तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया गया है, अधिनियमों के, जो कि इस निमित्त बनाये जायें, अध्याधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार किया जायेगा और उसका उपयोग खनिज-धारित क्षेत्रों के विकास के लिये किया जायेगा।

खान पट्टा के अधीन की भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर का उद्गृहण.

**भाग ५—प्रकीर्ण.**

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावहील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार को आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से अलग न हो, दूर कर सकेगी :

कठिनाई दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवकाश हो अथवा  
का पश्चात्, नहीं किया जाएगा.

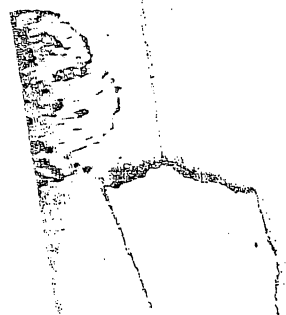
स्पष्टीकरण.—इस धारा में प्रामाण्यिक "इस अधिनियम के प्रारंभ होने" से, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध  
के संबंध में, अभिमत है प्रारंभ होने की वह सुसंगत तारीख जो उस उपबन्ध के संबंध में धारा १ की  
उपधारा (३) के अधीन नियत की गई हो.

नियम बनाने की  
शक्ति.

- ११. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम पूर्व प्रकाशन के  
पश्चात् बना सकेगी.
- (२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जायेंगे.

भोपाळ, दिनांक ६ मई १९८२

क. ११६६४-इन्फोस-म (भा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्य प्रदेश सरकारान  
अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १४ मई १९८२) का प्रथम प्रतुभाय राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.  
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ज. म. खर, विशेष सचिव.



MADHYA PRADESH ACT

No. 10 of 1982

THE MADHYA PRADESH KIRADHAN ADHONYAM, 1982

Sections :

TABLE OF CONTENTS

PART I—PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

2. Definitions.
3. Levy of School Building cess.
4. Constitution of primary school buildings construction fund.
5. Maintenance and operation of fund.

PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

6. Definitions.
7. Levy of forest development cess on sale or supply of forest produce.

PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

8. Definitions.
9. Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

PART V—MISCELLANEOUS

10. Power to remove difficulty.
11. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 1982

THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAM, 1982.

[Received the assent of Governor on the 3rd May, 1982; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 6th May, 1982.]

An Act to provide for levy of school building cess, forest development cess and mineral areas development cess and matters incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

PART I—PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

2. In this part, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(b) "school building cess" means the school building cess levied under section;

(c) "holder of land" means a tenure holder, occupancy tenant or a Government lessee;

(d) "holding" means all land held by a holder in the State in any one or more than one of the capacities specified in clause (c);

(e) "member of a Schedule Caste" means a member of any caste, race or tribe or part of a group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(f) "member of Schedule Tribes" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(g) words and expressions used in this part and not defined herein but defined in the Code shall have the meaning assigned to them in the Code.

3. (1) There shall be levied and collected for every revenue year school building cess on every holding of six hectares and above held by a holder at the rate of three rupees and seventy five paise per hectare:

Levy of school building cess.

Provided that the provision of this sub-section shall, in respect of a holding held by a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall, have effect as if for the words "six hectares", the words "ten hectares" were substituted.

(2) The school building cess levied and collected under sub-section (1) shall be in addition to land revenue or rent or any other cess or tax payable by the holder of the land in respect of the holding under the Code or any other enactment for the time being in force and shall be payable by the holder of the land in the same manner as, and along with, land revenue.

(3) The provisions of the Code relating to assessment, collection and recovery of land revenue shall, so far as may be, apply to the assessment, collection and recovery of school building cess under this part as if the cess were land revenue assessed on the holding under the Code.

4. (1) The proceeds of the school building cess under section 3 shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the school building cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Primary School Buildings Construction Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

Constitution of Primary School Buildings Construction Fund.

(2) The State Government shall every year make its contribution to the fund equal to fifty per cent. of the amount credited to the fund under sub-section (1).

(3) The amount in the credit of the fund shall be utilised for construction and furnishing of Primary School building in non-urban areas as defined in clause (2-z) of section 2 of the Code and for that purpose only so much amount in the credit of the fund shall be allotted to a district as is recovered by way of school building cess from that district together with fifty per cent. of the contribution of the State Government for that district.

5. The maintenance and operation of the Primary School Buildings Construction Fund, including the investment or re-investment of sums in its credit, shall be in accordance with the rules made under this Part.

Maintenance and operation of Fund.

### PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

6. In this Part,—

(a) "forest development cess" means cess levied on sale or supply of forest produce by the Forest Department under section 7;

(b) "Forest Department" includes the Forest Development Corporation constituted under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);

(c) the expression "forest produce" shall have the meaning assigned to that expression in clause (4) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927);

Definitions.

7. (1) There shall be levied and collected a forest development cess on every sale or supply of forest produce by the Forest Department at the rate of one per cent. of the price at which such forest produce is sold or supplied.

Levy of forest development on sale or supply of forest produce.

(2) The forest development cess levied under sub-section (1) shall be in addition to any tax leviable on forest produce under any other law for the time being in force.

(3) The forest development cess payable under sub-section (1) in respect of forest produce sold or supplied by the Forest Department shall be payable by the person to whom the forest produce is sold or supplied and shall be collected by and recovered by the officer or official of the Forest Department concerned with such sale or supply at the time of such sale or supply.

(4) The proceeds of the forest development cess levied under sub-section (1) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the forest development cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Forest Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

(5) The amount in the credit of the fund shall, at the discretion of the State Government, be utilised for—

- (a) social forestry purposes;
- (b) afforestation, re-forestation and rehabilitation of forest; and
- (c) any other purposes connected with the development of forests, as the State Government may, by notification, specify.

(6) The maintenance and operation of the Forest Development Fund shall be in accordance with the rules made in this behalf.

#### PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

##### Definitions

8. In this part, unless the context otherwise requires,—

- (a) "dead rent" means the dead rent payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957);
- (b) "land" means land held under a mining lease for undertaking mining operations;
- (c) "mineral areas development cess" means cess levied under section 9 on land held under a mining lease for undertaking of mining operations;
- (d) "royalty" means the royalty payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957) and includes any payments made or likely to be made to the Central Government or the State Government as the case may be for the right of raising minerals from the land under the said Act;
- (e) words and expressions used but not defined in this part and defined in the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957) shall have the same meanings as in that Act.



10 (10) 37 10 30 601

9. (1) There shall be levied and collected on the land held under a mining lease for undertaking mining operation a mineral areas development cess at the rate of twenty five per centum of the rental value thereof. Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

(2) For the purpose of sub-section (1) rental value shall be equal to the royalty or dead rent as the case may be, whichever is higher.

(3) The mineral areas development cess shall be payable by the person to whom the mining lease is granted.

(4) The mineral areas development cess shall, subject to and in accordance with the rules made in this behalf, be collected by such agencies and in such manner as may be prescribed and shall be applied towards development of mineral bearing areas.

PART V—MISCELLANEOUS

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty. Power to remove difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of one year from the date of commencement of this Act.

Explanation.—In this section the expression "commencement of this Act" means with relation to any provision of this Act, the relevant date of commencement, appointed under sub-section (3) of section 1, in relation to that provision.

11. (1) The State Government may, after previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the State Legislative Assembly.